The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 1 | January 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

आई.सी.टी. के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन को बढ़ाना: ई-गवर्नेंस नवाचारों के कार्यान्वयन की एक व्यवस्थित जांच

अभय शुक्ला
शोध छात्र, मानवीय विद्या शाखा , पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग,
उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords:
आईसीटी, ई-गवर्नेंस, ग्रामीण प्रशासन , ग्रामीण विकास, नवाचार

ABSTRACT

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो की संचार का नवीनतम साधनों में से एक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक व्यापक शब्द जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इंटरनेट और कंप्यूटर से संचालित होने वाले संचार साधनों का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो यह प्रौद्योगिकी का एक हिस्सा है परंतु प्रतियोगिकी के सहायता से यह संचार और भागीदारी का विस्तृत स्वरूप है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसे आम भाषा में आईसीटी कहा जाता है उसका प्रयोग सरकार द्वारा अपनी योजनाओं और सेवाओं का सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए किया जाए या प्रशासन के कार्यों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए उसे ई-गवर्नेंस या ई प्रशासन कहते हैं। ई-गवर्नेंस ने एक जिम्मेदार और पारदर्शी प्रशासन की नीव रखने का काम किया है, इसके अंतर्गत नागरिकों की सीधी भागीदारी प्रशासनिक क्रियाकलापों में होती है उसे प्रत्येक चरणों की पूरी जानकारी उपलब्ध होती रहती है। वैसे तो ई-गवर्नेंस को चार हिस्सों में बांटा गया है G2C (Government to Citizens),G2B (Government to Business),G2E (Government to employees) और G2G (Government to Government), भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत 1970 ई से शुरू है परंतु इसका पूर्ण रूप वर्ष 2000 के बाद

अस्तित्व में आया। भारत में इसका पहली बार जिक्र द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के रिपोर्ट के अंतर्गत किया गया था। यह शोध पत्र G2C ई-गवर्नेंस सेवाओं पर केंद्रित है। आईसीटी संचार का एक हिस्सा है इसी तरीके से ई-गवर्नेंस भी संचार का ही भाग है इसे संचार के क्षेत्र में नवाचार के रूप में देखना तनिक मात्रा भी गलत नहीं होगा, इस शोध कार्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण प्रशासन में प्रयोग की जाने वाली ई-गवर्नेंस सेवाओं के लाभ और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है साथ ही साथ जानने का प्रयास किया गया है कि नवाचार के रूप में ई-गवर्नेंस सेवाओं का ग्रामीण नागरिकों के बीच प्रसार का स्तर क्या है। इस अध्ययन में वर्णनात्मक शोध विधि के अंतर्गत गुणात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है । आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए पूर्ण में किए गए अध्ययनों (शोध पत्र), प्रकाशित रिपोर्ट और समाचार पत्रों और वेब में प्रकाशित खबरों का सहयोग लिया गया है।

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.14848299

- **प्रस्तावना**

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसे आमतौर पर आईसीटी के नाम से भी जाता है। यह प्रौद्योगिकियों के व्यापक रूप को संदर्भित करता है जो सूचना के प्रबंधन और प्रसारण यानी संचार की सुविधा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उपकरणों, अनुप्रयोगों और प्रणालियों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो जानकारी को इकट्ठा करने, भंडारण करने और प्रसार करने के लिए सक्षम बनाती है। सूचना के आदान-प्रदान के लिए बाधा रहित नेटवर्क बनाने के लिए आईसीटी द्वारा दूरसंचार, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सहित विभिन्न प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया जाता है। आई.सी.टी. आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और प्रशासन विशेष कर सरकारी जैसे विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए शिक्षा में

आई.सी.टी. ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम और ऑनलाइन संसाधनों की सुविधा प्रदान करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यह रोगी प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन में सहायता करता है। व्यवसाय के क्षेत्र में कुशल संचार, डेटा विश्लेषण और प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए आई.सी.टी. का लाभ उठाया जाता हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं और सार्वजनिक सूचना प्रसार के लिए आई.सी.टी. का उपयोग करती हैं। आई.सी.टी. की निरंतर प्रगति ने व्यक्तियों और संगठनों द्वारा संचार करने के तरीके में परिवर्तन लाया हैं। इंटरनेट, मोबाइल प्रौद्योगिकियों और क्लाउड कंप्यूटिंग के आगमन ने दैनिक जीवन में आई.सी.टी. के उपयोग को और वृद्धि कर दिया है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) ने ग्रामीण प्रशासन की दक्षता और पहुंच को बढ़ाकर इसकी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अतीत में ग्रामीण क्षेत्रों को सीमित संचार बुनियादी ढांचे के कारण शासन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। हालाँकि मोबाइल एप्लिकेशन और इंटरनेट सेवाओं जैसे आई.सी.टी. उपकरणों के एकीकरण ने इस अंतर को पाट दिया है। आई.सी.टी. द्वारा सूचना के प्रसार की आसान सुविधा प्रदान की जाने से प्रशासनिक सेवक द्वारा नीतियों, सेवाओं और अद्यतनों को तेजी से संप्रेषित करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस और प्रबंधन प्रणालियाँ द्वारा रिकॉर्ड-कीपिंग को सुव्यवस्थित करती हैं जो आंकड़ों की सटीकता और निर्णय लेने में सुधार करती हैं।

ग्रामीण प्रशासन

ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय शासन और सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन एवं प्रशासन शामलित है। इसमें ग्रामीण समुदायों के विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाने वाले योजना, संसाधन और नीतियों के कार्यान्वयन जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। इसके प्रमुख घटकों में कृषि उत्पाद विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और बुनियादी ढांचा शामिल हैं। एक प्रभावी ग्रामीण प्रशासन सदैव सतत

विकास को बढ़ावा देता है जो ग्रामीण निवासियों को सशक्त बनाता है और उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। जैन एल.सी. (1988) जैसे विद्वान ग्रामीण विकास में विकेंद्रीकृत निर्णय लेने और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में पंचायती राज प्रणाली विकेंद्रीकृत ग्रामीण प्रशासन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है (ड्रेज़ और सेन, 2002)। समावेशी विकास को बढ़ावा देने और शहरी-ग्रामीण असमानताओं को पाटने के लिए ग्रामीण प्रशासन की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण प्रशासन का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का समाकलन होने से ग्रामीण प्रशासन प्रक्रिया अत्यधिक सुगम हो सकती है इसके द्वारा शासन और सेवा वितरण को बढ़ाने में अत्यधिक सहयता मिलेगी। आईसीटी उपकरण जैसे मोबाइल एप्लिकेशन और इंटरनेट-आधारित प्लेटफ़ॉर्म से कुशल संचार, डेटा प्रबंधन और संसाधन आवंटन जैसे कार्यों को करने के लिए सक्षम करती हैं। यह सूचना को समय पर प्रसार करने ग्रामीण समुदायों और इससे संबंधित पदाधिकारी को सशक्त बनाने की सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भारत में ई-ग्रामस्वराज, ई-ग्राम पंचायतग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ग्रामीणों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सीधे तौर पर भागीदारी देते हुए स्थानीय शासन को सुव्यवस्थित और सशक्त किया है। इसके साथ ही आईसीटी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योजना, स्वास्थ्य प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्र में सरलता से नागरिकों तक पहुंच बनता है। किसानों के लिए बाजार से बेहतर कनेक्टिविटी और उससे संबंधित जानकारी तक वास्तविक समय पर पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे किसान को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। आईसीटी और ग्रामीण प्रशासन का अभिसरण द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी शासन को बढ़ावा मिला है।

ग्रामीण प्रशासन में ई-गवर्नेंस

यूनेस्को के अनुसार "शासन का तात्पर्य किसी देश के मामलों के प्रबंधन में राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्राधिकार के प्रयोग से है, जिसमें नागरिकों द्वारा उनके हितों की अभिव्यक्ति और उनके कानूनी अधिकारों और दायित्वों का प्रयोग शामिल है। ई-गवर्नेंस को जनता और अन्य एजेंसियों तक सूचना प्रसारित करने की एक कुशल, त्वरित और पारदर्शी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और सरकारी प्रशासन गतिविधियों को

निष्पादित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से इस शासन के प्रदर्शन के रूप में समझा जा सकता है।"

चेतिया, के. (2020) आईसीटी का उपयोग ग्रामीण लोगों को अपने सार्वजनिक मामलों को निष्पादित करने, सार्वजनिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद करता है ताकि वे राष्ट्र के नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित कर सकें।

स्ट्रेटिगि, ए.(2011) आईसीटी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कई पहलुओं में योगदान दे सकते हैं जैसे कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, सुरक्षित भोजन का उत्पादन, व्यवसायों और उद्यमिता का समर्थन, स्थानीय श्रम के कौशल और दक्षताओं का उन्नयन और साथ ही साथ स्थानीय समाज में संबंधों को मजबूत करना।

ग्रामीण प्रशासन में ई-गवर्नेंस की उपयोगिता को एक परिवर्तनकारी प्रारंभ के रूप में देखा जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई सार्वजनिक सेवाओं और योजनाओं तक नागरिकों की पहुंच और साथ ही में उसकी दक्षता को भी बढ़ने का कार्य करता है । ग्रामीण प्रशासन में ई-गवर्नेंस के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता ली जाती है जो प्रशासनिक कार्यों को करने में अत्यधिक सहायक साबित होता है। इसे डिजिटल उपकरणों की मदद से प्रधानता प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बना सकते हैं जिससे ग्रामीण नागरिकों तक दूर दराज के क्षेत्र में भी इसकी पहुंच सरल की जा सके । ग्रामीण प्रबंधन में इसकी प्रमुख भूमिका भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन, कृषि विस्तार सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाए और शिक्षा के क्षेत्र जैसे विभिन्न प्रशासनिक प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन होता है। उपरोक्त सेवाओं को डिजिटलीकरण करने से निर्णय लेने में तेजी आई है कागजी कार्रवाई कम होने से और और लोगों का कार्रवाइयों तक सीधी पहुंच होने के कारण से पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है जिससे शान प्रक्रिया में सम्मिलित लोगों की जवाबदेही बनी है । ई-गवर्नेंस के आने से नागरिक आज मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग से सीधे शासन के साथ जुड़ाव करने का सुविधा मिल सका है इसके कारण ही आज ग्रामीण नागरिक का जानकारी तक पहुंचे बनने के साथ-साथ ही शिकायत दर्ज करने और स्थानीय निर्णय में भागीदारी करने की साक्षमता बन सकी है ।

उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया पहला ने ई-गवर्नेंस सेवाओं को बढ़ावा देकर ग्रामीण प्रशासन पर एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है । ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सेवा केंद्र सीएससी सेवा वितरण बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है जो सरकारी सेवाओं का ग्रामीण नागरिकों तक सरल पहुंच बनता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) क्या प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण समुदाय में रहने वाले लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर एवं सक्षम बनाने का है उन्हें ई-गवर्नेंस टूल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना है ।

- **अध्ययन का महत्व**

इस अध्ययन का महत्व ई-गवर्नेंस नवाचारों के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन को बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के प्रयोग और उसे होने वाले लाभ की खोज में निहित है। ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन और प्रभाव की जांच करना यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी कैसे कुशल शासन प्रथाओं में योगदान दे सकती है और ग्रामीण सेटिंग्स में संभावित रूप से आईसीटी कैसे अद्वितीय चुनौतियों का समाधान कर सकती है। यह शोध ग्रामीण समुदायों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शासन उपकरणों और प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। जो अंततः समावेशी और प्रभावी शासन रणनीतियों की प्रगति में योगदान देगा।

- **साहित्यिक समीक्षा**

रॉबर्ट चैंबर्स (1979) द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक "रूरल डेवलपमेंट: पुटिंग द लास्ट फर्स्ट" के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए जमीनी स्तर पर ग्रामीण नागरिकों की भागीदारी और समुदाय के नेतृत्व के लिए विकसित की गई पहल के महत्व पर प्रकाश डाला है । चैंबर्स के अनुसार विकास के पारंपरिक के तरीके के द्वारा ग्रामीण विकास संभव नहीं है जिसके अंतर्गत टॉप-डाउन दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता था उनके द्वारा इस सिद्धांत की आलोचना की गई है और बॉटम-अप दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने की सिफारिश की जाती है । उनके

अनुसार ग्रामीण प्रशासन से संबंधित निर्णय निर्णय लेने की प्रक्रिया में हाशिए पर रखे जाने वाले समूह को प्राथमिकता देने की आवश्यक है जिसमें विशेष कर महिलाएं और गरीबों को शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है । चैंबर्स ने सदैव अधिक भागीदारी और समावेशी दृष्टिकोण की वकालत किया है जिसके अंतर्गत शासन और प्रशासन ग्रामीण आबादी के साथ उनकी चुनौतियों और आकांक्षाओं को समझने के लिए सक्रिय रूप से जुड़ा रहेगा । वह ग्रामीण क्षेत्र की भौगोलिक एवं आर्थिक विविधता को समझते हुए विकास की रणनीति में सदैव लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया हैं।

हीक्स (2006) द्वारा अपने पुस्तक "एंप्लॉयमेंटिंग और मैनेजिंग ई-गवर्नेंस :एन इंटरनेशनल टेक्स्ट" के अंतर्गत तर्क दिया गया है की शासन में अंतर्गत डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा सूचना और सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करके व्यवस्थापकों द्वारा ग्रामीण विकास के बढ़ोतरी में काम करके ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाया जा सकता है। लेखक ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सेवा वितरण कार्यकर्मों, और शासन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आईसीटी के प्रोयोग पर जोर दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बुनियादी रूप से प्रारंभ करने में आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डाला है। हील्स के अनुसार यह संभावना जताया जाता है कि ग्रामीण संदर्भों में ई-गवर्नेंस सेवाओं को प्रारंभ करने में बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक कारकों का बाधा के रूप में सामना करना पड़ेगा । पुस्तक में दी गई संभावनाएं ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को कम करने में आईसीटी को प्रभावी ढंग से उपयोग के रणनीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो समावेशी विकास को बढ़ावा देती है और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करती है।

भटनागर (2004) में अपनी पुस्तक "ई-गवर्नेंस: फॉर्म विजन तो इंप्लीमेंटेशन - ए पार्क्टिकल गाइड विथ कैसे स्टडीज" में इस बात पर जोर देते हैं कि शहरी ग्रामीण असमानता को समाप्त करने के लिए और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ई- गवर्नेंस की क्षमताओं का प्रयोग ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत करने पर जोर देना चाहिए। उनके अनुसार प्रौद्योगिकी विकास प्रक्रिया को से व्यवस्थित कर सकती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली सेवाओं का बेहतर वितरण किया जाना संभव हो सकेगा ।

सिंह, ए. (2014). इस शोध कार्य के अंतर्गत भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में शासन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर संबंध पर प्रकाश डाला गया है यह पेपर वर्तमान परिदृश्याम में ई-गवर्नेंस के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की चुनौतियां और प्रयासों को संदर्भित करते हुए भविष्य के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह शोध पत्र में बताया गया है कि आईसीटी द्वारा ई-गवर्नेंस भारत में एक महत्वपूर्ण एजेंडा के रूप में उभरा है जिसका उद्देश्य नागरिक को तक सूचना और सेवाओं की पहुंच बढ़ाना एवं उनमें सुधार करना है।इस अध्ययन के अनुसार ई-गवर्नेंस में यूपी राज्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यहां की सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की ई-गवर्नेंस योजनाओं को अस्तित्व में लाया गया है जो योजनाएं गरीबी उन्मूलन और विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। परंतु केंद्र सरकार और अन्य राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर नहीं है, शोधकर्ता का सुझाव है की राज्य भर में परियोजनाओं/अनुप्रयोगों को लागू करने और उनका समर्थन करने के लिए यूपी सरकार को बड़े प्रयासों की आवश्यकता है।

वानी, एम., और तांत्रे, जेड.आई. (2018) अपने अध्ययन के अंतर्गत शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया है की भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र की भागीदारी तीव्र गति से बढ़ रही है इसके कारण के तौर पर उनके द्वारा बताया गया कि भारत की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। शोध पत्र में प्रकाश डाला गया है कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी को प्रयोग में लेते हुए विभिन्न परियोजनाओं की नींव रखा है । वर्ष 2020 तक भारत सरकार लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापक नागरिक सरकार संपर्क हासिल किया जा सके, इसके लिए सरकार पहले से ई-चौपाल, किसान कॉल सेंटर, आकाशगंगा, ज्ञान दूध और टाटा किसान केंद्र जैसी पहलो को प्रारंभ कर चुकी है। यह शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ों के सहायता से ई-गवर्नेंस को बढ़ाने में आईसीटी प्रौद्योगिकी की भूमिका के संबंधित मुद्दों पर चर्चा किया है ।शोध के निष्कर्ष के रूप वर्णन किया गया कि भारत जैसे तहसील देश भारत जैसे विकासशील देश में डिजिटल विभाजन को खत्म करने में ई-गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आईसीटी ई-गवर्नेंस और डिजिटल

इंडिया सहित चल रहे अन्य सरकारी परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक नेटवर्क और भागीदारी के द्वारा ग्रामीण सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्रामीण समुदाय में पारदर्शिता के साथ बुनियादी सुविधाओं को किफायती दर में प्रदान करने के लिए एक गवर्नेंस का उपयोग आवश्यक माना गया है इसी के साथ ही ई-गवर्नेंस में आईसीटी का सफल अनुप्रयोग ग्रामीण समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए व्यापक संविधान के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

अग्रवाल और मेहरोत्रा (2017) में अपने शोध के अंतर्गत ई-गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए कहा कि सार्वजनिक सेवा विशेष कर सरकारी सेवाएं प्रदान करने और अपने नागरिकों तक पहुंचाने के लिए आई.सी.टी. का उपयोग करना ई - गवर्नेंस सेवाएं कहलाती हैं। उनका यह अध्ययन ई-गवर्नेंस सेवाओं के लाभ और बढ़ाओ के बारे में नागरिकों के परिपेक्ष और ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाले साइटों के उपयोग के प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत लोगों को तीन समूह में विभाजित कर दिया गया है अत्यधिक सुविधायुक्त, सकारात्मक विचारधारा वाले एवं तटस्थ विचारक के रूप में देखा गया है। अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि उत्तरदाताओं को उन ई-गवर्नेंस सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी है जो उन्हें सीधे प्रभावित करती है जबकि जो इन सेवाओं के परिणाम स्वरुप सरकार के प्रदर्शन से संबंधित होती है उन्हें उत्तरदाताओं में काम जागरूकता देखी गई है। अग्रवाल और मल्होत्रा के अनुसार सरकार को ई-गवर्नेंस के प्रति लोगों में जागरूकता स्तर को बढ़ाने की जरूरत है जिससे जनता बड़े पैमाने पर इन साइटों का उपयोग करेगी। उनके अनुसार गोपनीयता का मुद्दा एक सबसे बड़ी बाधा के रूप में लोगों में ई-गवर्नेंस के प्रयोग के प्रति है सरकार को लोगों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी गोपनीयता बरकरार रहेगा और उनके आंकड़ों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। इस शोध कार्य में यह भी देखने को पाया गया कि समूह 2 में जो ई-गवर्नेंस सेवा साइटों को उपयोग करने के प्रति अधिक सकारात्मक उत्तरदाताओं के अनुसार की सेवाएं शासन के प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कदम है वहीं समूह 1 के उत्तरदाता में ई-गवर्नेंस सुविधा का प्रयोग उच्च स्तर पर था क्योंकि इन लोगों के पास ही गवर्नेंस सेवा सीटों का उपयोग करने के लिए आवश्यक

सुविधाएं है। समूह एक और तीन के अनुसार गोपनीयता का मुद्दा ईगवर्नेंस में सबसे बड़ी बाधा है, वही समूह दो के उत्तरदाताओं में ऑनलाइन कनेक्टिविटी टूल्स को सबसे बड़ी बाधा के रूप में पाया गया है।

चेतिया, के. (2020) ने अपने शोध कार्य के अंतर्गत बताया है कि ई-गवर्नेंस का उद्देश्य कल्याणकारी कार्यक्रम को कुशलता पूर्ण लागू करना और सरकारी सेवाओं को 24/7 किस प्रकार नागरिकों के लिए सक्षम बनाया जा सके इस पर जोर देता है। ई-गवर्नेंस नागरिकों तक सरकारी परियोजनाओं और दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच करने के कारण नागरिकों तक इसकी पहुंच सरल हो गई है। ईश्वर पत्र के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की जांच की गई है जो ग्रामीण विकास में ई-गवर्नेंस की भूमिका को स्पष्ट करते हैं और संबंधित चुनौतियां को भी समक्ष लाते हैं। इस शोध पत्र में समाज के भीतर ई-गवर्नेंस के द्वारा डिजिटल भिन्नता को कम करने में सक्षम माना गया है परंतु इसके लिए सरकार को आईसीटी , डिजिटल इंडिया और सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों द्वारा ग्रामीण सशक्तिकरण में इसका योगदान लेना होगा । शोधकर्ता द्वारा निष्कर्ष के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने विशेष रूप से ई-गवर्नेंस के लिए आईसीटी अनुप्रयोग में लोगों की भागीदारी बढ़ाना ग्रामीण विकास के लिए मिल का पठार साबित हो सकता है जो ग्रामीण समुदाय में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के लिए व्यापक समाधान प्रदान करेगा ।

टोयामा, के. (2011). के अध्ययन के क्षेत्रों में एक प्रमुख क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को किस प्रकार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रभावित करता है, इन्होंने प्रौद्योगिकी द्वारा सामाजिक और मानवी कारकों के समाधानों को समझना पर जोर दिया है। इनको इन्होंने तर्क दिया कि प्रौद्योगिकी अकेले जटिल समस्या सामाजिक मुद्दों से संबंधित समस्याओं को हल नहीं कर सकती है, लेकिन वह व्यक्तियों और समुदायों के इरादों और क्षमताओं को बढ़ा सकती है टोयामा ने आईसीटी के द्वारा ग्रामीण विकास के संदर्भ में कहते हैं कि "हालांकि आईसीटी विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है लेकिन यह अकेले इतना सशक्त नहीं है इसका उपयोग अन्य विकास रणनीतियों के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए वह स्थानीय संदर्भ और समुदाय की जरूरत को समझते के महत्व पर जोर देना चाहिए।" टोयामा के अनुसार विकास

के प्रक्रिया कभी भी किसी एक वस्तु या तकनीकी पर आधारित न होकर समग्र दृष्टिकोण अपनाने और उससे संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक कारकों पर विचार करने से प्राप्त होते हैं।

सिंह, एस. के., और मेधावी, एस. (2021) इस अध्ययन कार्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और सफलताओं से संबंधित है संबंधित है। यह शोध पत्र वर्णनात्मक दृष्टिकोण का है जिसके अंतर्गत द्वितीयक आंकड़ों को प्रयोग में लिया गया है। प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की सफलता और उनके सकारात्मक प्रभाव के बावजूद, अभी भी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तकनीकी और गोपनीयता संबंधित कई चुनौतियां बनी हुई है। इस शोध पत्र में सलाह दिया गया है कि ई-गवर्नेंस की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी योजना के स्थानीय स्तर पर फायदे और नुकसान की गहन समाज महत्वपूर्ण है योजनाओं के अंतर्गत स्थानीय समुदाय विशेष रूप से युवाओं को शामिल करना चाहिए और उन्हें ई-गवर्नेंस के लाभों के बारे में अवगत कराने की जरूरत है। ई-गवर्नेंस सेवाओं से संबंधित पदाधिकारी की भी परीक्षण के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी समर्थन भी सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक शर्तें हैं । शोधकर्ता का सुझाव है कि ई-गवर्नेंस सेवाओं को उपयोगकर्ता के अनुकूल पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है लोकतांत्रिक ई-गवर्नेंस नागरिकों के विश्वास को बढ़ाएगा और अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ प्राप्त होगा ।

- **शोध उद्देश्य**

1. ग्रामीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण प्रशासन में की गई विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों का अध्ययन करना।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीटी के माध्यम से विकास की राह में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।

3. किन तरीको से ई- गवर्नेंस को नवाचार के रूप में ग्रामीण निवासियों के बीच प्रसारित किया जा सकता है ।

- अनुसंधान क्रियाविधि

यह शोध कार्य गुणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत द्वितीयक आंकड़ों के सहयोग से किया गया है, इस शोध कार्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को नमूने के तौर पर लिया गया है। इस अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान तकनीक का उपयोग व्यवस्थित रूप से घटित होने वाली प्रक्रिया की व्याख्या करने में किया गया। यह तकनीक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस की व्याख्या से संबंधित सूचना, आंकड़े ,तथ्य उत्पन्न करती है। इस शोध के अंतर्गत आंकड़ों को प्रकाशित शोध पत्रों, रिपोर्टों और अन्य सरकारी वेबसाइटों द्वारा एकत्र किया गया है ।

- **परिणाम और चर्चा**

1- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख 30 ई-गवर्नेंस सेवाएं चलाई जाती हैं जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और शहरी दोनों प्रशासनिक कार्यों पर केंद्रित है। ग्रामीण प्रशासन से संबंधित ई-गवर्नेंस सेवाएं जैसे ई-पंचायत, भूलेख, आपूर्ति, ई-डिस्ट्रिक, आईजीआरएस जन सुनवाई, महिला सम्मान कोश आदि नागरिकों को सुविधा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। साहित्य समीक्षा के दौरान सिंह, ए. (2014) अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में ई-गवर्नेंस सुविधा की पहुंच और प्रदर्शन, केंद्र और अन्य राज्यों की तुलना में बेहद निचले स्तर की थी परंतु पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा कई बार पुरस्कृत किया गया है। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में **मां नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन** के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। NeSDA 2021 के मूल्यांकन मापदंडों में 85 प्रतिशत से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्य में स्थान पाया हैं। यह स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में ई-गवर्नेंस सुविधा पिछले कई वर्षों के प्रयासों के बाद अब यह नागरिकों में एक बेहतर सेवा प्रदान कर पा रही हैं ।

2- अध्ययन के दौरान यह पता चलता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच डिजिटल विभाजन एक बड़ा मुद्दा है जिसके कारण कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में आईसीटी के माध्यम से विकास कार्यों में बाधा आती है। बुनियादी ढांचे, लोगों में जागरूकता और विश्वास की कमी ग्रामीण क्षेत्र में आईसीटी के प्रयोग में

सबसे बड़ा बाधा है। उत्तर प्रदेश के सरकार के योजना विभाग द्वारा सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाई गई "विजन-2030" के अंतर्गत सिर्फ 10 बार ई-गवर्नेंस सेवाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें से सिर्फ एक बार ग्रामीण क्षेत्र में ई-पंचायत सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कहा गया है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्र को विशेष कर वहां के युवाओं को केंद्रित करके ई-गवर्नेंस सेवाओं के प्रति जागरूकता, उससे होने वाले लाभों और उसकी सरल प्रक्रिया के बारे में बताने की आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को इन सेवाओं के प्रति सहज महसूस करवाना प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए।

3- ई-गवर्नेंस की शुरुआत वैसे तो 1970 की दशक से हो गई थी परंतु तब के समय में की गवर्नेंस का स्वरूप एक तरफ संचार युक्त था। वर्तमान ई-गवर्नेंस का स्वरूप भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है ई-गवर्नेंस को नवाचार के रूप में देखना बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा, रोजर्स द्वारा दिए गए सिद्धांत "नवाचार का प्रसार" में जिस प्रकार किसी नवाचार को लोगों के बीच पहुंचने में विभिन्न चरणों की आवश्यकता होती है इस प्रकार ई-गवर्नेंस को भी लोगों में सामान्य करने के लिए कुछ प्रमुख चरणों की आवश्यकता है। अध्ययन के दौरान यह पता चलता है कि लोगों में अभी ई-गवर्नेंस के प्रति जागरूकता की कमी स्पष्ट देखने को मिलती है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण लोक अभी डिजिटल उपकरणों के साथ सहज महसूस नहीं करते परंतु ऐसा नहीं है कि पूरे ग्रामीण समाज में ऐसा देखने को पाया जाता है युवा और संपन्न वर्ग डिजिटल उपकरणों का प्रयोग बड़ी मात्रा में कर रहे हैं कमी है तो सिर्फ भागीदारी की, सरकार को ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह ई-गवर्नेंस सेवाओं के प्रति अपनी रुचि बढ़ाएं और इसे अपने जीवन उसका प्रयोग करें ।

- **निष्कर्ष**

ग्रामीण प्रशासन में आईसीटी के अंतर्गत ई-गवर्नेंस एक प्रकार का नवाचार है इसके विस्तार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रयास किया जा रहे हैं परंतु यह प्रयास अधिक विशिष्ट नहीं हो कर अधिक सामान्य

है। शहरी और ग्रामीण परिवेश की समस्याओं में भिन्नता होने के कारण यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिपूर्ण नहीं है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक केंद्रित होते हुए प्रशासन क्रियाकलापों में ई-गवर्नेंस के लिए विशेष योजनाओं को लाने की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। सरकार को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण केंद्रों को बनवाना चाहिए और उन केंद्रों में युवाओं की भागीदारी को अधिक से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। अध्ययन में यह देखने को पाया गया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी में बड़ा अंतर देखने को पाया जाता है यद्यपि पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा इस कम करने के लिए अनेकों प्रयास किया जा रहे हैं जैसे मोबाइल फोन वितरण, लैपटॉप वितरण आदि, और यह प्रयास कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर सफल होते भी दिख रहे हैं।

सुझाव एवं सीमाएं- यह शोध कार्य पूर्व में प्रकाशित शोध पत्र, सरकारी रिपोर्ट और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर किया गया है। अतः इसे पूर्ण स्पष्ट नहीं माना जा सकता है पूर्ण स्पष्ट अध्ययन के लिए सर्वेक्षण, साक्षात्कार और सीधे तौर पर अवलोकन किए गए अध्ययन की आवश्यकता है।

- **ग्रंथ सूची**

1- Heeks, R. (2006). Implementing and managing e-government: An international text (pp. 75-89). Sage.

2- Bhatnagar, S. (2004). E-government: From vision to implementation – A practical guide with case studies (pp. 120-135). Commonwealth Secretariat.

3- Toyama, K. (2011). Technology as amplifier in international development. Association for Computing Machinery. New York, NY, United States.

4- Singh, A. (2014). E-governance Initiatives in Uttar Pradesh. Asian Journal of Technology & Management Research, 4(1), ISSN: 2249-0892.

5- Singh, S. K., & Medhavi, S. (2021). E-Governance in Uttar Pradesh: Concept, Initiatives and Challenges. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology, 9(3), ISSN: 2321-9653.

6- Chetia, K. (2020). E-Governance for Rural Development: Assessing the Impact of E-Governance Initiatives and Projects in Rural India. Journal of Critical Reviews, 7(4), ISSN-2394-5125.

7- Agarwal, R., & Mehrotra, A. (2017). E-Government Services in an Emerging Economy: A Citizen's Perspective. Amity Journal of Corporate Governance,2 (1), 49-62.

8- Chambers, R. (1979). Rural Development: Putting the Last First. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.

9- Wani, M., & Tantray, Z. I. (2018) ICT and its role in e-governance and rural development: An Indian perspective Source. Transformational Managerial Skills: National Press Associates.

10- https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1950617

11- https://up.gov.in/en/article/key-e-governance-project

12- https://doi.org/10.4000/netcom.144

13- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1833276

14- https://smartcity.eletsonline.com/five-e-governance-portals-of-uttar-pradesh-get-awarded/

15- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1833331

16- https://vikaspedia.in/e-governance/states/uttar-pradesh

17- https://www.nic.in/blogs/measuring-rural-e-governance/